हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 12 दिसंबर 2025, समय 1305 (05 मिनट)

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के साथ बैठक के बाद खत्म हो गई है। हरियाणा के चिकित्सकों के संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई दो दौर की बैठक के बाद चिकित्सकों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की ।

स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के बाद चिकित्सक संगठन के प्रधान डॉक्टर राजेश ख्यालिया ने बताया कि ACP को लेकर सरकार ने एक विकल्प दिया है।इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती और और ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति न होने पर भी चिकित्सक को एसीपी देने पर भी सहमति बनी है

हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक मनीष बंसल ने कहा है कि चिकित्सकों ने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित न करने का आश्वासन दिया है।

हरियाणा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए विश्व बैंक ने हरियाणा की सतत विकास के लिए स्वच्छ वायु परियोजना के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मंज़ूर की है।यह परियोजना 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। स्वीकृत सहायता में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं

विकास बैंक ऋण तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकृत बहु दाता कोश से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान विश्व बैंक ने सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2,498 करोड़ रुपये का ऋण देने का आश्वासन दिया था। परियोजना की कुल लागत 3,646 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,065 करोड़ रुपये का योगदान हरियाणा सरकार करेगी और अतिरिक्त 83 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य परिवहन, उद्योग, कृषि, शहरी प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार करना है। परियोजना में परिवहन क्षेत्र के लिए 1,688 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनका लक्ष्य शहरी परिवहन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाना और राज्य के स्वच्छ मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इस अंतर्गत 1,513 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने एवं स्क्रैपिंग इकोसिस्टम के लिए, 20 करोड़ रुपये 200 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, 100 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर प्रोत्साहन और 45 करोड़ रुपये पुराने थ्री-व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने हेतु गाड़ी बदलने के लिए प्रोत्साहन पर व्यय किए जाएंगे। उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा 563 करोड़ रुपये स्वच्छ औद्योगिक संचालन, रियल-टाइम उत्सर्जन नियंत्रण एवं अनुपालन सुधार पर खर्च किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में 746 करोड़ रुपये कृषि एवं विकास तथा पंचायत विभागों के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। इनमें 2030 तक पराली जलाने को समाप्त करने के लिए 280 करोड़ रुपये, बायो-डीकंपोजर तकनीकों पर अनुसंधान हेतु 52 करोड़

रुपये, कृषि विभाग में एक द्वितीयक उत्सर्जन निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए 151 करोड़ रुपये, तथा पशु अपशिष्ट से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने हेतु स्वच्छ खाद प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए 263 करोड़ रुपये का खर्च शामिल हैं। इसी तरह, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने एवं वैज्ञानिक-नियामक आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए 564 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

पलवल जिला की उप-तहसील हसनपुर में कल जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होडल से विधायक हरेंद्र सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं, शिकायतों एवं आवेदनों की सुनवाई की गई। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया --

---